



'सु-शहरीकरण': महत्त्व और चुनौतियाँ

यह एडटोरियल 20/09/2021 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Why India needs 'good' urbanisation" लेख पर आधारित है। इसमें शहरीकरण से संबद्ध समस्याओं की चर्चा की गई है और विचार किया गया है कि 'सु'-शहरीकरण ('Good' Urbanisation) कर्सि प्रकार इन समस्याओं को हल कर सकता है।

संदर्भ

शहरों को प्रायः गरीबी उन्मूलन की एक तकनीक के रूप में देखा जाता है; आँकड़ों की मानें तो न्यूयॉर्क शहर की समग्र जीडीपी रूस की जीडीपी के समान है, जबकि न्यूयॉर्क में रूस की तुलना में केवल 6% आबादी और 0.00005% भूमि ही मौजूद है।

हालाँकि कोवडि-19 महामारी ने ग्रामीण इलाकों की उस धारणा को प्रोत्साहन दिया है, जिसमें माना जाता है कि एक तकनीक के रूप में शहर, प्रवासियों के प्रति उनकी शत्रुता, रोग संक्रमण हॉटस्पॉट प्रवृत्ति और डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप कार्य की घटती हुई केंद्रीयता के कारण अवांछनीय हैं।

कानून, कोवडि-19 को हमारे शहरों को अधिक शक्ति और धन के साथ सशक्त बनाकर 'सु-शहरीकरण' (Good Urbanization) को उत्प्रेरित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

डिटिट: द वजिार्ड vs प्रोफेट

- शहरों का 'वांछनीय या अवांछनीय' होना पोस्ट-कोवडि समय में बहस के एक विषय के रूप में उभरा है। यह 1960 के दशक में भोजन के बारे में उभरी एक बहस की याद दिलाता है जिसे चार्ल्स मान (Charles Mann) की महत्त्वपूर्ण कतिाब 'द वजिार्ड एंड द प्रोफेट' में समेटा गया था।
- नॉर्मन बोरलॉग (Norman Borlaug)—यानी 'द वजिार्ड'—एक नोबेल वैज्ञानिक हैं, जिनका मानना था कि विजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी चुनौतियों का सामना कर लेंगे और उन्होंने वैश्वकि स्तर पर कृषि क्षेत्र में हरति क्रांति का आगाज़ किया था।
- वलियम वोग्ट (William Vogt)—यानी 'द प्रोफेट'—का मानना था कि समृद्धि इंसानों को मतिव्ययता का अवसर दिये बनिए बर्बाद कर देगी और इस प्रकार उन्होंने प्रयावरण संरक्षण आंदोलन का आगाज़ किया था।
- जहाँ एक और नॉर्मन बोरलॉग ने 'नवप्रवर्तन' (Innovation) का नाम दिया, वहीं वलियम वोग्ट ने पीछे हटने (Retreat) का आहवान किया।

शहरीकरण: एक समाधान या समस्या

- यदि शहरीकरण की प्रक्रिया एक उचित समय-सीमा के भीतर घटती होती है, तो यह कई सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार, शहरीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभावों में रोजगार के अवसरों का सृजन, तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक प्रगति, बेहतर परविहन एवं संचार, गुणवत्तापूरण शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधाएँ और जीवन स्तर में सुधार आदिशामिति हैं।
- वहीं यदि शहरीकरण की प्रक्रिया लंबे समय तक अनियमित रूप से जारी रहती है तो इसके कुछ प्रत्यक्षील प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
 - शहरीकरण लोगों को नगरों और कस्बों की ओर आकर्षित करता है जिससे उच्च जनसंख्या वृद्धि होती है। शहरी केंद्रों में वास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ आवासों की नरितर कमी की स्थितिबनती है।
 - महानगर या मेगास्टी (10 मिलियन से अधिक आबादी) उन लोगों के लिये एक चुनौतीपूरण स्थितिपैदा करती है, जो अमीर या शक्ति-संपन्न नहीं है।
 - बेरोजगारी की समस्या शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है और शक्तिपैदा लोगों के बीच यह और भी गंभीर होती है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर के आधे से अधिक बेरोजगार युवा महानगरीय शहरों में रहते हैं।
 - शहरी क्षेत्रों में नवाच की लागत बहुत अधिक होती है। जब यह लागत, अपरत्याशति वृद्धितथा बेरोजगारी के साथ मलिती है तो इससे गरीब लोगों की चुनौतियाँ और भी गंभीर हो जाती हैं और अवैध बस्तियों का प्रसार होता है।
- विश्व की 33 मेगास्टीज़ में से 26 विकासशील देशों में हैं, क्योंकि उनके ग्रामीण क्षेत्रों में विधि के शासन, आधारभूत अवसंरचना और उत्पादक वाणिज्य की कमी होती है। इसके अतिरिक्त, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेगास्टीज़ के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र अनुपयुक्त योजना, गैर-

अनुमेय अवसंरचना, कफियती आवास की कमी और बदतर सार्वजनिक परविहन जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।

- हालांकि, मेगास्टीज अनविएरय रूप से चुनौतीपूरण नहीं होती है। उदाहरण के लिये टोक्यो में जापान की आबादी का लगभग एक-तहिई हसिसा भौजूद है, किंतु वहाँ योजना एवं निवास के माध्यम से ऐसी व्यवस्था निर्मिति की गई है, जिसमें शिक्षक, नर्स और पुलिसिकर्मी जैसे आवश्यक कर्मचारियों को कार्यस्थल के लिये शायद ही कभी दो घंटे से अधिक की यात्रा करनी पड़ती हो।
 - शहर की गुणवत्ता के लिये सबसे व्यावहारिक मीट्रिक इतालवी भौतिक वजिआनी 'सेसारे मार्चेटी' (Cesare Marchetti) ने पेश किया है जो मानते हैं कि 30 मिनट सबसे स्वीकार्य, या कहा जाए सभ्य यात्रा समय होता है (जबकि पैदल यात्रा से लेकर साइकिल, ट्रेन और कारों ने परविहन का तरीका बदल दिया है)।
 - बंगलुरू जैसे शहर में 'मार्चेटी स्थरिंग' (Marchetti Constant) को लागू करना लगभग असंभव ही है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक के कारण टैक्सी और ऑटो 8 किमी/घंटे की औसत गति से चलते हैं।

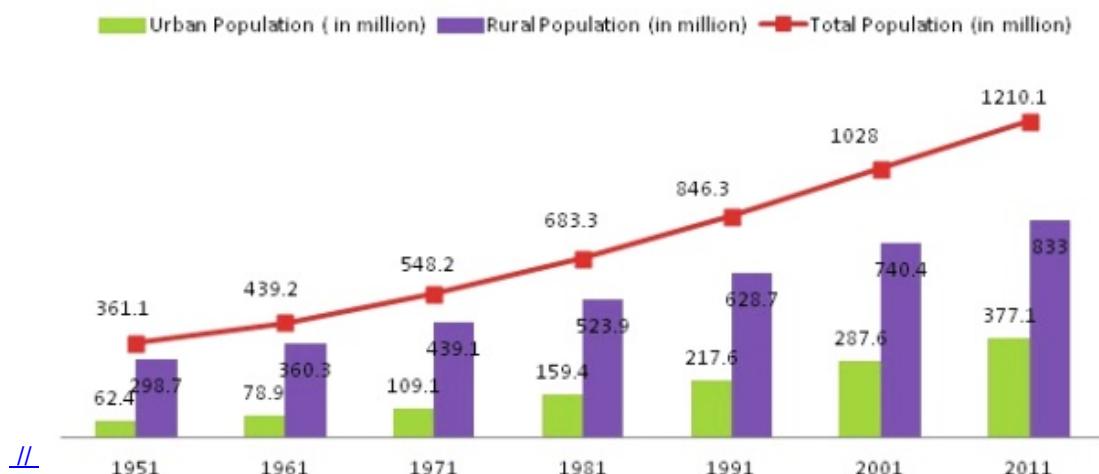
भारत में शहरीकरण की प्रमुख समस्या: कमज़ोर स्थानीय शहरी निकाय

- केंद्र सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 34 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का कुल वार्षिक व्यय लगभग 40 लाख करोड़ रुपए वही 15वें वित्ती आयोग के अनुमान के मुताबिकि, 2.5 लाख से अधिक स्थानीय निकाय प्रतिवर्ष केवल 3.7 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करते हैं।
- इस असमान व्यय के कई कारण हैं:
 - **बजिली:** राज्य सरकार के विभागों द्वारा पानी, बजिली, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा आदिविषयों को लेकर स्थानीय सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है (यदनिगर निकायों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाए तो संपत्ति कर संग्रह 100% होगा)।
 - **स्वायत्त:** ग्रामीण एवं शहरी निकायों के बजट का केवल करमश: 13% और 44% ही स्वयं के प्रयास से जुटाया गया था।
 - **संरचना:** प्रायः राज्यों को यह अस्वीकार्य होता है कि उनके वित्त एवं शासन संबंधी मामलों को कसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाए, लेकिन राज्य सरकार स्वयं, स्थानीय निकायों पर असीमित नियंत्रण का प्रयोग करती है (अधिकांश राज्यों में महापौरों एवं अन्य नियंत्रित प्रतिविधियों का नलिंबन या उन्हें पद से हटाना अथवा नियंत्रित स्थानीय निकायों का अधिकृतमण एक सामान्य स्थिति है)।
 - अलग-अलग केंद्रीय ग्रामीण और शहरी मंत्रालयों का होना नीतिको विकृत करता है।
 - **बेहतर नेतृत्व की कमी:** शक्ति एवं संसाधनों की कमी एक खतरनाक दुष्यकर की शुरुआत कर देती है, जहाँ महत्त्वाकांक्षी एवं प्रतिभाशाली लोगों को शहरों में नेतृत्व के लिये आमंत्रित नहीं किया जाता है।

आगे की राह- सु-शहरीकरण की आवश्यकता

- **सामाजिक-आर्थिक न्याय हेतु:** महलियों, बच्चों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के लिये आर्थिक न्याय सुनाशीचति करने हेतु सु-शहरीकरण बेहद महत्त्वपूरण है।
 - खराब गुणवत्ता वाले शहरीकरण के परणिमस्वरूप केवल पुरुषों का प्रवास होता है, जहाँ महलियों को कृषकियों, बच्चों के पालन-पोषण और परविहार वालों की सेवा के लिये पीछे छोड़ दिया जाता है। उनके पास न तो स्वास्थ्य सेवाओं का कोई आश्रय होता है, न ही वे जीवनसाधी का भावनात्मक समर्थन पाने में सक्षम होती हैं।
 - खराब गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूलों में जाने वाले ग्रामीण बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या सविलि सेवाओं के लिये अंग्रेजी-प्रधान प्रवेश परीक्षाओं में भाषा संबंधी चुनौतियों का सामान करते हैं।
 - कसी भी मानक पर सर्वोत्कृष्ट नहीं होने के बावजूद शहरों में स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा दोनों की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर है।
- **छोटे और मध्यम शहरों का पुनर्विकास:** इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेगास्टीज के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र अनुपयुक्त योजना, गैर-अनुमेय अवसंरचना, कफियती आवास की कमी और बदतर सार्वजनिक परविहन जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।
 - इस प्रकार छोटे एवं मध्यम शहरों पर ध्यान केंद्रित किये बना सु-शहरीकरण संभव नहीं है।
- **शहरों को शक्तिओं और धन प्रदान करना:** सु-शहरीकरण के लिये राज्य सरकार को अपने स्वारथ का त्याग करने की आवश्यकता है। इससे उच्च गुणवत्तापूरण नौकरियों और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद मिल सकती है।
 - भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा है कि 'खाद्य प्रौद्योगिकी' बहस में 'नॉर्मन बोरलॉग' ने 'विलियम वोगट' पर जीत हासिल की है यानी 'नवप्रवर्तन' की जीत हुई है।
 - चूंकि पोस्ट-कोवडि समय में शहरीकरण की बहस गतिपकड़ रही है, हम आशा करते हैं कि एक बार फिर 'प्रोफेट' पर 'विजिरड' की जीत होगी।

Growth of Urban Population Since 1951-2011 in India



अभ्यास प्रश्न: 'कोवडि-19 महामारी इस बात को पुष्ट करती है कि निर्धनता कम करने हेतु सु-शहरीकरण हमारे सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक है। टपिपणी कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/good-urbanisation>